



Major approaches to the study of india's foreign policy

1 message

ANJANI GHOSH <anjanighosh51@gmail.com>
To: econtentofarts@gmail.com

Thu, Aug 13, 2020 at 8:09 AM

भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण :-

एक राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार के सम्बन्ध रखकर अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता है यही विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरे राज्यों से अपने सम्बन्धों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का कार्यान्वयन ही विदेश नीति है। जे. आर. चाइल्डस ने इसे 'वैदेशिक सम्बन्धों का आधारभूत तत्व माना है, और राजनय (Diplomacy) को विदेश नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया कहा है।

प्रो. हिल के अनुसार- "विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है।"

श्लाइचर के शब्दों में- "अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है, जो एक राज्य अपने बाह्य सम्बन्धों को संचालित करने के लिए करता है।"

जार्ज मौडेल्स्कि ने विदेश नीति की परिभाषा करते हुए लिखा है- "विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था।"

रोडी तथा क्रिस्टल के अनुसार- "विदेश नीति के अन्तर्गत ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्द्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है।"

फैलिक्स ग्रीस के शब्दों में- "अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनायी गयी विशिष्ट क्रिया पद्धति (System of actions) है।"

अमरीकी राजदूत हजगिब्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विदेश नीति की राहें' (The Road to Foreign Policy) में लिखा है कि विदेश नीति नियोजन (Planning) है। उनके मत में विदेश नीति जानकारी और अनुभव पर आधारित एक सर्वतोमुखी व्यापक योजना है, जिसके अनुसार एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करता है। विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों का विकास और संरक्षण करना होता है।

हैण्डरसन के अनुसार- "विदेश नीति राष्ट्रीय परम्पराओं से संचालित होती है। समस्याओं का अलग-अलग समाधान विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित होती है।

बुकिंग शोध संस्थान के मत में- "विदेश नीति एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ अपने सम्बन्धों में पालन की जाने वाली एक संश्लिष्ट (Complex) और गतिशील राजनीति विद्या (Course) है। राष्ट्र की विदेश नीति उसकी विदेश नीतियों के समस्त योग से अधिक होती है क्योंकि विदेश नीति में उस राष्ट्र की वचनबद्धता, हितों और लक्ष्यों का वर्तमान स्वरूप तथा उसके द्वारा घोषित उचित आचरण के (आदर्श) सिद्धान्त भी निहित होते हैं।"

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि, विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है, जिनका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है, और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करना है, और यदि यह सम्भव न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है, जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रियाकलापों के साथ तालमेल बैठ सके।

विदेश नीति: अध्ययन के दृष्टिकोण (Approaches to Foreign Policy):-

किसी भी देश की विदेश नीति का किस दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाये यह प्रश्न सदैव विवादास्पद रहा है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में विदेश नीति के विभिन्न विद्वानों-विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। इन सभी दृष्टिकोणों के बारे में यहां जानकारी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। इस कारण जो मुख्य-मुख्य दृष्टिकोण हैं उनके बारे में चर्चा करना समीचीन होगा।

विदेश नीति के बारे में प्रमुख रूप से चार दृष्टिकोण निम्नांकित हैं:-

- (1) सैद्धान्तिक दृष्टिकोण,
- (2) विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण,
- (3) मार्क्सवादी दृष्टिकोण और
- (4) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक दृष्टिकोण।

इनके बारे में विस्तृत विश्लेषण निम्नांकित है:

(1) सैद्धान्तिक दृष्टिकोण:

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि, राज्यों तथा उनके मुकाबले शेष विश्व की नीतियां मात्र प्रचलित राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्तियां हैं। इस

दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वान विदेश नीतियों को प्रजातान्त्रिक या सर्वाधिकारवादी उदारवादी या समाजवादी शान्तिप्रिय या आक्रामक, इत्यादि रूपों में वर्गीकृत करते हैं ।

यह दृष्टिकोण वैदेशिक सम्बन्धों व्यवहारों या आचरण को मुख्यतः मनोवैज्ञानिक रूप में स्वीकार करता है । नेताओं या सरकारों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों को नीति के एक पूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में नहीं तो भी आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करता है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार एक लोकतान्त्रिक शासन एक विशिष्ट प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण करता है तो एक निरंकुश तन्त्र भिन्न प्रकार की नीति को अपनाता है । इसी प्रकार एक साम्यवादी सरकार एक विशिष्ट प्रकार की नीति अपनाती है तो प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकार भिन्न प्रकार की नीति का अनुसरण करती है । इसका तात्पर्य यह है कि इस सैद्धान्तिक या वैचारिक दृष्टिकोण में विदेश नीति एक सक्रिय राजनीतिक नेताओं की आस्थाओं और रुचियों के अनुसार निर्धारित होती है ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का घटता प्रभाव:-

विदेशी नीति के इस सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का प्रभाव दिनोंदिन क्षीण होता जा रहा है । इस सिद्धान्त के आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक विश्व के देशों की सरकारें चाहे वे निरंकुश हों या लोकतान्त्रिक पूंजीवादी हों या समाजवादी-सभी सैद्धान्तिक तौर पर लोकतन्त्र और शोषण के विरोध की बातें करती हैं किन्तु व्यवहार में उनमें से कुछ सरकारें कम हद तक अधिनायकवादी एवं शोषक होती हैं ? तो कुछ ज्यादा मात्रा में अर्थात् सिद्धान्त का लिबास ओढ़कर शेष विश्व को आदर्शवाद का उपदेश देती हैं अन्यथा व्यवहार में ठोस एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की येनकेन-प्रकारेण पूर्ति करती हैं ।

राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते समय सरकारें यह नहीं देखतीं कि उनका सैद्धान्तिक रूप से घोषित उद्देश्य क्या है और किन गलत साधनों के जरिये अपनी आस्थाओं का अतिक्रमण करके वह विदेश नीतियां क्रियान्वित कर रही हैं ।

अमरीकी विदेश नीति का ही उदाहरण लें । अमरीका एक लोकतान्त्रिक देश है और दुनिया के लोकतान्त्रिक देशों को यथासम्भव सहायता देना उसका घोषित उद्देश्य है लेकिन वह लोकतान्त्रिक भारत के विरुद्ध अधिनायकवादी पाकिस्तान की मदद करता आया है । इस प्रकार विदेश नीति के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है ।

(2) विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण:-

पिछले कुछ वर्षों से अनेक विद्वानों ने विदेश नीति के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के औचित्य पर प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है, तब से विदेश नीति के कई विशेषज्ञों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है । इस सिद्धान्त के समर्थकों की मान्यता है कि, विश्व सरकारें विदेश नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानती हैं एवं अपने सामाजिक व राजनीतिक दर्शन धार्मिक दृष्टिकोण तथा सैद्धान्तिक विचारों को गौण इसलिए तो कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश का न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न स्थायी मित्र स्थायी सिर्फ राष्ट्रीय हित होते हैं ।

अर्थात् कोई भी देश राष्ट्रहितों की हर कीमत पर रक्षा करता है भले ही उसे अपने घोषित सिद्धान्तों का अतिक्रमण ही क्यों न करना पड़े। स्वयं अपने देश का ही उदाहरण लें। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य विश्वशान्ति एवं सुरक्षा रहा है। वह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करता है।

उसकी मान्यता है कि राष्ट्रों के बीच विचारों का हल युद्ध के द्वारा न होकर शान्तिपूर्ण वार्ता के द्वारा हो लेकिन जब 1962 में साम्यवादी चीन ने भारत पर बर्बर सैनिक आक्रमण कर दिया तो भारत ने उस युद्ध का जवाब भी युद्ध से ही दिया।

अतः जहां स्थूल राष्ट्रीय हितों की रक्षा का सवाल हो कोई भी देश वैचारिक आदर्श को गौण मानता है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि। इस प्रकार विदेश नीति का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अधिक प्रासंगिक माना जाता है लेकिन इस व्याख्या के साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि यह जरूरी नहीं कि हर समय राष्ट्रीय हितों और सिद्धान्तों में टकराव हो अनेक बार विश्व सरकारें घोषित सिद्धान्तों पर आधारित विदेश नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती हैं।

(3) मार्क्सवादी दृष्टिकोण:-

विदेश नीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण अत्यन्त निराला है। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने किसी भी नीति के मूल्यांकन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिया है। यदि विदेश नीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण को अपनाया जाये तो इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जायेगी।

मार्क्सवाद की विदेश नीति के सम्बन्ध में अनेक धारणाएं हैं। मसलन एक साम्यवादी देश दूसरे साम्यवादी देश की मदद करता है। पूंजीवादी देश गरीब देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। पूंजीवादी देशों की विदेश नीति साम्राज्यवादी नीतियां अपनाती है। इसी प्रकार की अन्य कई धारणाएं हैं जिनके आधार पर किसी भी देश की विदेश नीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अन्तर्विरोध:-

मार्क्स ने जो दृष्टिकोण दिया, उसे आगे के मार्क्सवादी चिन्तकों ने जहां एक ओर उसका विस्तार से विश्लेषण किया वहीं दूसरी ओर उस मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आंशिक परिवर्तन भी किये। साम्यवादी सोवियत संघ और चीन में सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रभाव और भी घटता जा रहा है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेज़नेव "एशियन सेक्यूरिटी प्लान" का विचार प्रस्तुत करते थे तो साम्यवादी चीन उसे मार्क्सवादी सिद्धान्तों के खिलाफ बताता था।

इसी प्रकार जब माओ ने अपनी 'थ्री वर्ल्ड थिसिस' में सोवियत संघ को प्रथम विश्व में रखकर उसको शोषक और अधीनस्थतावादी बताया तो सोवियत संघ ने माओ की इसके लिए आलोचना की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मतभिन्नता आने से अब इस दृष्टिकोण का महत्व दिनों-दिन घटता जा रहा है।

(4) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक दृष्टिकोण:-

परम्परागत रीति से विदेश नीति के अध्ययन का यह भी एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण वाले चिन्तकों की मान्यता है कि हमें कूटनीति का अध्ययन यथासम्भव अधिक से अधिक परिशुद्धता से करना चाहिए। वर्णनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में रुचि नहीं रखते। वे सामयिक घटनाओं पर विचार करने से कतराते हैं।

वे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में घटनाक्रम के तिथिवार वर्णन में विश्वास करते हैं। असल में यह दृष्टिकोण अत्यन्त पुराना है और एकांगी भी। इस दृष्टिकोण की मुख्य कमजोरी यह है कि यह राजनीतिक शक्ति और विदेश नीति के आपसी सम्बन्धों का महत्व कम करके आंकता है। इन्हीं कारणों से इस दृष्टिकोण का महत्व एकदम कम हो गया है।

विदेश नीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन:-

भारतीय विदेश नीति के अर्थ, परिभाषा एवम उपयुक्त चारों दृष्टिकोणों-सैद्धान्तिक, विश्लेषणात्मक, मार्क्सवादी और वर्णनात्मक – के विवेचन के बाद यह कहना उचित होगा कि इनमें से कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक दृष्टिकोण के कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण हैं। विदेश नीति आधुनिक युग में इतनी अधिक जटिल है कि इसे विभिन्न दृष्टिकोणों के बनावटी सैद्धान्तिक सांचों में ढालना मुश्किल है। अतः समय और परिस्थिति के अनुसार इसके दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता होती है यही परिवर्तन किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता का कारण है।